



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938

No. 124]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2016

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

विषय : चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एमोक्सिलीन" के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच

सं. 14/06/2015-डीजीएडी.—मै. अरविंदो फार्मा लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक/घरेलू उद्योग भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण. (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "एमोक्सिलीन" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु भी कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है।

2. और यतः प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि पाटनरोधी जांच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराने के लिए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य हैं, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच की शुरुआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

3. यह आवेदन घरेलू उद्योग के रूप में मै. अरविंदो फार्मा लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है।

4. रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार आवेदक कंपनी का उत्पादन घरेलू उत्पादन का 'प्रमुख हिस्सा' बनता है। अतः प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि आवेदक कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के अर्थ के भीतर पात्र घरेलू उद्योग हैं और आवेदन संबंधित नियमावली के नियम 5 (3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करता है।

विचाराधीन उत्पाद

5. जॉच में विचाराधीन उत्पाद 'एमोक्सिलीन' है।

6. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद एमोक्सिलीन ट्रिहाइड्रेट के रूप में भी जाना जाता है। एमोक्सिलीन ट्रिहाइड्रेट एक सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, जो अनेक ग्राम-पाजिटिव और ग्राम-नेगेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म के विरुद्ध बैक्टेरियासाइडल गतिविधि के व्यापक स्पेक्ट्रम के साथ एम्पीसिलीन का एक समकक्ष है।

7. एमोक्सिलीन का प्रयोग औषध-रोधी सूक्ष्मजीवों के विकास को कम करने के लिए किया जाता है। एमोक्सिलीन और अन्य प्रतिजैविक औषधों की प्रभाविकता को बनाये रखने के लिए, एमोक्सिलीन का प्रयोग केवल ऐसे संक्रमणों का उपचार करने के लिए किया जाता है जो सिद्ध या अत्यधिक संभावित रूप से बैक्टेरिया के कारण होते हैं।

8. एमोक्सिलीन के एक कार्बनिक रसायन होने के कारण उसे उपशीर्ष सं 29411030 के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और प्रस्ताविक जॉच और प्रस्तावित उपायों के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

9. आवेदक ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु और आवेदकों द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। जैसा आवेदकों ने बताया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं और कर रहे हैं। आवेदकों ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें 'समान वस्तु' माना जाना चाहिए। अतः प्राधिकारी वर्तमान जॉच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश/क्षेत्र से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' मानते हैं।

शामिल देश

10. वर्तमान जांच चीन जन. गण. (जिसे 'संबद्ध देश' भी कहा गया है) से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन से संबंधित है।

सामान्य मूल्य

11. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार देश माना जाना चाहिए और उसका सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। आवेदक ने भारत में उत्पादन लागत को विशिष्ट रूप से समायोजित करके चीन जन. गण. में सामान्य मूल्य का दावा किया है। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के अधीन कार्य कर रहे हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और चीन जन. गण. में प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है।

निर्यात कीमत

12. आवेदक द्वारा निर्यात कीमत का दावा डीजीसीआईएंडएस से प्राप्त सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध देश से भारत औसत आयात कीमत के रूप में किया गया है। निवल निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय भाड़े के व्यय, पटन व्यय और बैट के लिए कीमत संबंधी समायोजन किये गये हैं।

पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत के साथ की गई है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार निर्यात कीमत से अधिक है, जिससे यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है। इस प्रकार अनुमानित पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम सीमा से काफी अधिक है।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदकों ने समग्र रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में पाटित आयातों की बड़ी हुई मात्रा, कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, उत्पादन, बिक्री, बाजार हिस्सा, मालसूचियों में गिरावट के अनुसार भारी परिणामी प्रतिकूल प्रभाव के परिणाम के रूप में कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग द्वारा उठाई जा रही क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरुआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

15. आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन. गण. से आयात अचानक बढ़ गए हैं। अतः आवेदक ने दावा किया है कि आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होने का खतरा है। आवेदक ने पहले लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के बाद आयातों में भारी वृद्धि होने, आयात कीमतों में गिरावट, भारी आधिक्य क्षमता और संबद्ध देशों में उत्पादकों का काफी निर्यातान्मुख होने के बारे में संबद्ध आयातों से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति के खतरे के आधार के रूप में बताया है।

जांच अवधि (पीओआई)

16. इस जांच में जांच अवधि अक्टूबर 14 – सितम्बर 15 (12 महीनों) तक है। क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ, पिछले तीन वर्षों अप्रैल 2012- मार्च 2013, अप्रैल 2013- मार्च 2014, अप्रैल 2014- मार्च 2015 के आकड़ों और जांच की प्रस्तावित अवधि शामिल होगी।

सूचना प्रस्तुत करना

17. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं को निर्धारित प्रपत्र में एवं ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने तथा प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत कराने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है :—

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
चौथा तल ,जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग,
नई दिल्ली- 110001

18. कोई अन्य हितवद्ध पक्षकार भी जांच से संगत सूचना नीचे दी गई समय सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और पद्धति से प्रस्तुत कर सकता है।

समय-सीमा

19. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना और सुनवाई के लिए कोई अनुरोध इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है, तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार, "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

20. सभी हितवद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस जांच की शुरुआत की तारीख से 40 दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रभावली के अपने उत्तर दायर करें तथा पाटनरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत अथवा अन्यथा के बारे में घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें।

अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

21. यदि प्रश्नावली के उत्तर/अनुरोधों के किसी भाग के संबंध में "गोपनीयता" दावा किया जाता है तो ऐसे मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट (क) गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और (ख) अगोपनीय रूप में अंतिम दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि) प्रस्तुत करना होगा। दी गई समस्त सूचना पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए।

22. किसी गोपनीय अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी हितबद्ध पक्षों द्वारा गोपनीय पाठ की दो (2) प्रतियां और अगोपनीय पाठ की पाँच (5) प्रतियां प्रस्तुत करना जरूरी होगा।

23. गोपनीय होने का दावा की गई सूचना के लिए में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है और/या ऐसी सूचना का सारांशकरण क्यों संभव नहीं है।

24. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध / रिक्त छोड़ी गई और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

25. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

26. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

27. नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

28. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th April, 2016

INITIATION NOTIFICATION

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of 'Amoxycillin', originating in or exported from China PR.

No.14/06/2015-DGAD.—M/s Aurobindo Pharma Limited (hereinafter referred to as the applicant/ domestic industry) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as

the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti dumping duty concerning imports of Amoxycillin (hereinafter also referred to as the subject goods), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, 'injury' to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and 'injury' exist to justify initiation of an anti-dumping investigation; the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the 'injury' to the domestic industry.

Domestic Industry & Standing

3. The Application has been filed by M/s Aurobindo Pharma Limited as the domestic industry.

4. As per the evidence available on record, the production of the applicant company constitutes "a major proportion" of the domestic production. The Authority, therefore, determines that the applicant company constitutes eligible domestic industry within the meaning of Rule 2 (b) of the Anti Dumping Rules and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 (3) of the Rules supra.

Product under consideration

5. The product under consideration in the investigation is "Amoxycillin".

6. The product under consideration is also known as Amoxicillin Trihydrate. Amoxicillin Trihydrate is a semi synthetic antibiotic, an analog of ampicillin, with a broad spectrum of bactericidal activity against many Gram-positive and Gram-negative microorganisms.

7. Amoxicillin is used to reduce the development of drug-resistant bacteria. To maintain the effectiveness of Amoxicillin and other antibacterial drugs, Amoxicillin should be used only to treat infections that are proven or strongly suspected to be caused by bacteria.

8. Amoxicillin being an organic chemical is categorized under Chapter 29 of the Customs Tariff Act under sub-heading 29411030. The Customs classification is, however, indicative only and in no way binding on the scope of the proposed investigation and proposed measures.

Like Article

9. The applicant has claimed that there is no known difference between the subject goods exported from subject countries and that produced by the domestic industry. As submitted by the applicant, the product under consideration produced by the domestic industry and imported from subject country are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and are using the two interchangeably. The applicants have further claimed that two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the Authority treats the subject goods produced by the applicant in India as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject country.

Countries involved

10. The present investigation is in respect of alleged dumping of the product under consideration from China PR.

Normal Value

11. The Applicant has claimed that China PR should be treated as a non-market economy country and its normal value be determined in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The applicant has claimed normal value for China PR on the basis of cost of production in India, duly adjusted. In terms of Para 8 in Annexure 1 to the Rules it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non market economy conditions. In view of the above non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters from China PR, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

Export Price

12. The export price has been claimed by the applicant as the weighted average import price from subject country based on the transaction-wise import data obtained from the DGCI&S. Price adjustments have been made on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight expenses, port expenses and VAT to arrive at the net export price.

Dumping Margin

13. The normal value has been compared with the export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is higher than the ex-factory export price, indicating, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country. The dumping margin is estimated to be above de minimis.

Injury and Causal Link

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of increased volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting, price underselling and consequent significant adverse impact in terms of decline in production, sales, market share, inventories. There is sufficient prima facie evidence of the 'material injury' being suffered by the domestic industry caused by dumped imports from subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

15. The applicant has claimed that imports have spurted from China PR. The Applicant has therefore, claimed that the imports are threatening material injury to the domestic industry. The Applicant has submitted that there is significant increase in imports, decline in import price, significant surplus capacity and high export orientation of the producers in subject country as grounds for claiming threat of material injury to the domestic industry from subject imports.

Period of Investigation (POI)

16. The Period of Investigation (POI) proposed by the applicant is from 1st October 2014 to 30th September 2015 and the injury investigation period is for the periods, Apr'12-Mar'13, Apr'13-Mar'14, Apr'14-Mar'15 and the Period of Investigation. However, for enabling the Authority to make required analysis on the basis of more updated data, the Authority hereby determines the POI as 1st October 2014 to

31st December 2015 (15 Months). The injury investigation period will however, cover the periods 2012-13, 2013-14, 2014-15 and POI.

Submission of information

17. The known exporters in the subject country, the Government of the subject countries through their embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5 Parliament Street,
New Delhi -110001.

18. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

Time limit

19. Any information relating to the present investigation and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Anti-dumping Rules.

20. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application regarding the need to continue or otherwise the Antidumping measures within 40 days from the date of initiation of this investigation.

Submission of Information on Non-Confidential basis

21. In case confidentiality is claimed on any part of the questionnaire's response/submissions, the same must be submitted in two separate sets (a) marked as Confidential (with title, index, number of pages, etc.) and (b) other set marked as Non Confidential (with title, index, number of pages, etc.). All the information supplied must be clearly marked as either "confidential" or "non-confidential" at the top of each page.

22. Information supplied without any confidential marking shall be treated as non-confidential and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect any such non-confidential information. Two (2) copies of the confidential version and five (05) copies of the non confidential version must be submitted by all the interested parties.

23. For information claimed as confidential; the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed and/or why summarization of such information is not possible.

24. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out /summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in

exceptional circumstances, parties submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summarization; a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

25. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

26. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim may not be taken on record by the Authority. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided; shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

27. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

28. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority